# Jharkhand

*The land of the Forest*

Edited by Viren Lobo/ Sunil Dubey/ Tarun Kanti Bose/Hemant Das

On behalf of **IELA/JMKU/ ABMKSS**

*( The Political Ecology of Forests, Rivers, Mining and the people of Jharkhand)*

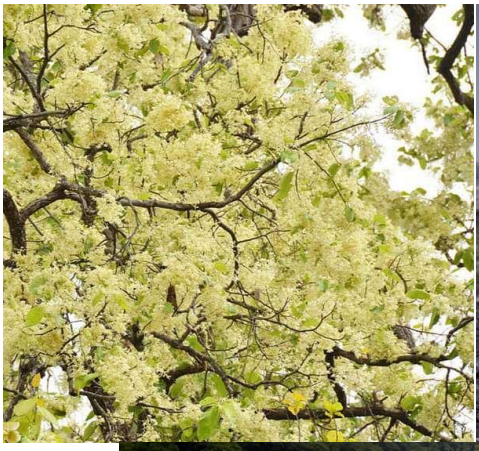

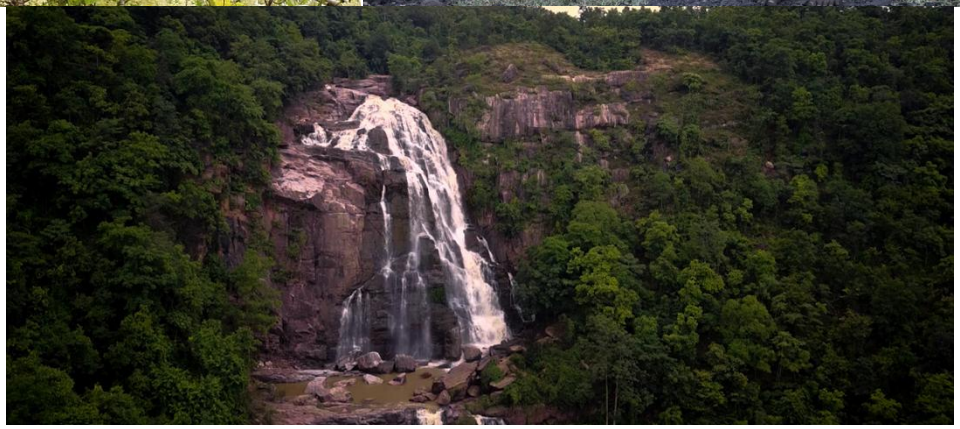

**The Sal tree/ Supratim Bhattacharya: Curse of mining/Hundru Falls**

# प्रस्तावना

झारखंड अर्थात जंगलों की भूमि 1765 में अंग्रेजों के समय ज्यादा प्रचलित हुआ | तब से आदिवासियों के द्वारा झारखण्ड में अंग्रेजो द्वारा उन पर लगाई गई कर प्रणाली के खिलाफ समय-समय पर संघर्ष होते रहे हैं । 1770 और 1785 के बीच संथालों द्वारा हूल विद्रोह और फिर 1855 में सिद्धू और कान्हु द्वारा अंग्रेजों को 1876 में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम लागू करने के लिए मजबूर किया गया । इसी प्रकार 1908 में छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम के लिए , बिरसा मुंडा एवं अन्य समुदायों द्वारा भी विद्रोह किए गए थे । संथाल , छोटानागपुर और कोल्हान, यह क्षेत्र लगभग हमेशा अंग्रेजों के साथ संघर्ष में रहता था। 1928 में, आदिवासियों के लिए एक अलग राज्य की मांग उन्नति समाज द्वारा रखी गई थी, जिसे बाद में 1938 में जयपाल सिंह मुंडा और अन्य लोगों ने आगे बढ़ाया । स्वतंत्रता के बाद भी 1955 में झारखंड के अलग राज्य की मांग की गई, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया क्योंकि आदिवासी अल्पसंख्यक थे । झारखंड ने आखिरकार 2000 में राज्य का दर्जा हासिल किया लेकिन बहुत जल्द लोगों को यह एहसास हो गया कि विकास के नाम पर लोगों को विस्थापित किया जा रहा है।

लोगों द्वारा किए गए इन शानदार संघर्षों और अंग्रेजों द्वारा अधिकारों की मान्यता को देखते हुए, झारखंड के आदिवासियों ने वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत अधिकारों की मान्यता की मांग में सक्रिय रूप से भाग नहीं लिया । हालांकि बाद में कई लोगों को महसूस हुआ की बाघ और हाथी के नाम पर शहरीकरण, खनन और वन संरक्षण के नाम पर हो रहे हमले के खिलाफ झारखंड के आदिवासियों के विविध संघर्ष को एक जुट करने का तरीका था । वन अधिनियम 1927 और वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत कथित उल्लंघन के कारण आदिवासियों के अपराधीकरण के माध्यम से गंभीर दमन, राज्य के कई क्षेत्रों में एफआरए लाभुक को जेल, अधिकारों से वंचित होने के परिणामस्वरूप हुआ है। राज्य में एक आदिवासी पार्टी के सत्ता में होने के बावजूद, हिरासत में मौत, यातना और गलत तरीके से कैद करना जारी है।

इसका कारण खोजना कठिन नहीं है। इस देश के केवल 2.4% भूमि क्षेत्र के साथ, झारखंड में देश के 40% खनिज संसाधन हैं, जिनमें से अधिकांश राज्य के वन क्षेत्रों में स्थित हैं । वास्तव में यह अफवाह है कि झारखंड राज्य आखिरकार इसलिए बनाया गया ताकि पटना में बैठे राजनेताओं और नौकरशाहों को रिश्वत न देनी पड़े । निश्चित रूप से 2000 में झारखंड के गठन के बाद से जिस तरह से शासन चला है, वह इस अफवाह को बल देता है। खनिज दोहन और वन संरक्षण की आवश्यकता का दोहरा हमला सरकार को आदिवासियों को उनके वाजिब हकों से वंचित करने के लिए उपयोगी उपकरण और साधन प्रदान करता है। इस आश्वासन के बावजूद कि एफआरए के तहत चिंताओं का विधिवत ध्यान रखा जाएगा, वन संरक्षण नियमों में संशोधन ने इसे और भी गंभीर मामला बना दिया है।

नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी में हालिया विकास, स्थानीय खाद्य पदार्थों के मूल्य को बढ़ावा देना और COVID 19 जिसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर दिहाड़ी मजदूरों का पलायन यहां से आगे बढ़ने की ओर इशारा करता है। वैज्ञानिक ज्ञान से युक्त पारंपरिक ज्ञान को उचित आकार और दिशा देना अब स्थायी रूप से संभव हो गया है, जो समुदायों को उन ऐतिहासिक टिप्पणियों में शामिल सिद्धांतों की पहचान करने में मदद कर सकता है, जो उनके द्वारा प्रदान किए जाने वाले पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के साथ मनुष्य के संबंध से संबंधित हैं। ग्राम सभाओं को फिर से सक्रिय करने की आवश्यकता, निहित स्वार्थों के प्रति-राजनीतिक दबाव भी इस प्रक्रिया में सशक्त महिलाओं और बच्चों की प्रासंगिकता और आवश्यकता को सामने लाते हैं। अस्तित्व से संबंधित वर्तमान चिंताओं ने इन लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को नीचा दिखाया है जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान नेतृत्व खंडित और असंगठित है। पेशा , जैव विविधता अधिनियम 2002 और एफआरए 2006 के प्रावधानों का उपयोग करके स्थानीय स्वशासन के सिद्धांतों में विश्वास बहाल करके इसे कैसे पुन: सक्रिय किया जा सकता है, यह वर्तमान में खोजा जा रहा है।

# पृष्ठभूमि

झारखंड मजदूर किसान यूनियन (जेएमकेयू) का गठन 2017 में अखिल भारतीय मजदूर किसान संघर्ष समिति (एबीएमकेएसएस) के कहने पर विकास के कॉरिडोर रूप का विरोध करने की प्रक्रिया के तहत किया गया था, जब विकास के नाम पर सरकार ने देश के व्यापक हित में स्थानीय समुदायों का अधिकारों का हनन करते हुए स्वतंत्र रूप से भूमि अधिग्रहण करना चाहती थी | शुरुआत में, जेएमकेयू ने एफ आर ए तहत अपने अधिकारों की मांग करने वाले आदिवासियों के अपराधीकरण का मुद्दा उठाया | और इसी के साथ एफ आर ए के तहत वर्णित समुदायों के अधिकारों से वंचित बताया | विभिन्न अधिनियमों और प्रावधानों के तहत आदिवासियों, मछुआरों और श्रमिकों को संगठित करते हुए, JMKU ने न केवल आदिवासियों की स्थितियों पर प्रकाश डाला, बल्कि झारखंड में पलामू, लातेहार और गढ़वा जिलों के डाल्टनगंज कमिश्नरी में अन्य संघर्षरत समुदायों को भी उजागर किया। जेएमकेयू एआईएफएफआरएस (ऑल इंडिया फोरम फॉर राइट्स स्ट्रगल) का हिस्सा बन गया और राज्य के अन्य संगठनों के सहयोग से पूरे झारखंड राज्य में इन मुद्दों पर संघर्ष तेज कर दिया। 2018 में, एबीएमकेएसएस के हिस्से के रूप में, देश भर में विकेंद्रीकृत शासन के लिए आदिवासियों को उनके संघर्ष में एकजुट करने की दृष्टि से बनाई गई आदिवासी भारत महासभा के गठन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी ।

जेएमकेयू के काम को तरुण कांति बोस द्वारा लिखी गई दो रिपोर्टों में चित्रित किया गया है, जो देश के ग्यारह राज्यों में एफआरए के कार्यान्वयन की स्थिति को समझने के लिए एआईएफएफआरएस द्वारा किए गए अध्ययन के हिस्से के रूप में पहली है। दूसरा एबीएमकेएसएस द्वारा किया गया एक अध्ययन पांच समुदायों के लिए एक रोड-मैप को परिभाषित करने के लिए किया गया है, जैसे आदिवासी, छोटे और पारंपरिक मछुआरे, पशुपालक, छोटे और सीमांत किसान और गांव से उत्पन्न होने वाले दिहाड़ी मजदूर। इन समुदायों की स्थितियों पर प्रकाश डालते हुए 'हाशिए पर लेकिन पराजित नहीं' शीर्षक वाला यह अध्ययन संघ, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर इन संघर्षों के एकीकरण के लिए एक रोड-मैप भी प्रदान करता है। यह अध्ययन मई 2022 में आदिवासी भारत महासभा (एकता मंच) के निर्माण को एक ऐसे स्थान के रूप में प्रस्तावित करने का आधार था जिसने इन संघर्षों में सबसे आगे स्थानीय संघर्षों और स्थानीय समूहों को मान्यता प्रदान की।

सितंबर 2022 में, एबीएम (यूएफ) के सदस्यों ने उदयपुर में मुलाकात की और विकेंद्रीकृत शासन के सिद्धांतों को साकार करने के लिए एक दोहरी रणनीति का प्रस्ताव रखा। पहले में निहित स्वार्थों की मिलीभगत से राज्य द्वारा दमन और आदिवासियों को झूठे मामलों में फंसाकर उनके अपराधीकरण, अत्याचार और अन्य अत्याचारों से संबंधित मुद्दों से निपटना शामिल था। दृष्टिकोण तय करने के लिए सितंबर से दिसंबर तक की अवधि को प्रारंभिक प्रकृति का मानते हुए, जेएमकेयू ने स्वेच्छा से जमीन पर दृष्टिकोण का अनुवाद करने के लिए अप्रैल में एक जन सुनवाई आयोजित की।

अपनी जमीनी तैयारी के तहत जेएमकेयू ने डाल्टनगंज कमिश्नरी में आदिम जनजाति कमजोर जनजातीय समूहों के बीच एक अभियान चलाया है। अभियान ने निम्नलिखित विषयों पर प्रकाश डाला है;

क. सामान्य रूप से एफआरए और विशेष रूप से सीएफआर का कार्यान्वयन न होना

ख. आवास की स्थिति में गिरावट के परिणामस्वरूप इसके पुनरुद्धार के लिए बाहरी समर्थन की आवश्यकता |

ग. भले ही इन समुदायों के लिए आकर्षक पैकेज तैयार किए जाते हैं, वे भ्रष्टाचार से ग्रस्त हैं, जिससे वे स्थानीय समुदायों के लिए पहुँच से बहार हो जाते हैं। उन्हें स्थानीय स्वशासन के सिद्धांतों के अनुकूल बनाने की आवश्यकता में ऐसे पैकेजों के डिजाइन और पारंपरिक स्वास्थ्य और पोषण प्रथाओं के पुनरुद्धार से संबंधित पहलू भी शामिल हैं।

# Dedication

Jaipal Singh Munda

https://indianhistorycollective.com/jaipal-singh-munda-historyofindia-constituent-assembly-adivasirights/

**"पृथ्वी पर सबसे लोकतांत्रिक लोग": संविधान सभा में एक आदिवासी आवाज।**

जयपाल सिंह मुंडा एक खिलाड़ी, लेखक और आदिवासी नेता थे। एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में संविधान सभा के लिए चुने गए, वह अपने समय में, भारत के आदिवासी समुदाय की ओर से बोलने वाली कुछ आवाजों में से एक थे। भाषणों में, वह समुदाय के लिए भारत के 'मूल निवासी' होने का मामला बनाता है, जो अति प्राचीन काल से बाहरी लोगों द्वारा शोषित और बेदखल किया गया है। वे संविधान सभा में, विशेष रूप से 16 मई के कैबिनेट मिशन वक्तव्य के तहत गठित सलाहकार समिति में, आदिवासी प्रतिनिधित्व की कमी की ओर भी ध्यान दिलाते हैं। लोगों के ऐतिहासिक दुर्व्यवहार के खिलाफ विरोध दर्ज करते समय, इन भाषणों को संकेतों के साथ विरामित किया जाता है भारत के नए नेतृत्व में उनका विश्वास और देश में बेहतर इलाज (और भागीदारी) की उम्मीद बनने वाली है।

जयपाल सिंह मुंडा बौद्धिक और शारीरिक रूप से एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। जैसा कि संविधान सभा में उनके भाषणों से पता चलता है, वे उस समय आदिवासी अधिकारों के लिए

एक भावुक और मुखर आवाज थे, जब उन्होंने सदियों से शोषण का सामना किया था, और उन्हें अंग्रेजों द्वारा आधुनिक राजनीतिक प्रक्रिया से दूर रखा गया था।

रांची के खूंटी उपखंड (अब, जिला) में प्रमोद पाहन के रूप में जन्मे, आदिवासी आइकन बिरसा मुंडा के समान उन्होंने अपना नया नाम तब प्राप्त किया जब उन्होंने इंग्लैंड के चर्च के एसपीजी मिशन द्वारा संचालित सेंट पॉल स्कूल में दाखिला लिया । . उन्होंने स्कूल में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और उनकी प्रतिभा ने एक मिशनरी, कैनन कॉसग्रेव को प्रभावित किया, जिसके साथ वे इंग्लैंड गए । वहां, उन्होंने 1926 में सेंट जॉन्स कॉलेज, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में सम्मान की डिग्री के साथ स्नातक किया। विश्वविद्यालय में अपने समय के दौरान, वह ऑक्सफोर्ड इंडियन मजलिस के अध्यक्ष भी थे, जो कि भारतीय छात्रों द्वारा स्थापित एक डिबेटिंग सोसाइटी है ।

एक प्रतिभाशाली हॉकी खिलाड़ी, मुंडा को 1928 के ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम की कप्तानी करने के लिए कहा गया था, जब वह भारतीय सिविल सेवा के लिए एक परिवीक्षाधीन के रूप में काम कर रहे थे । वह भारत कार्यालय के विरोध के बावजूद सहमत हुए, और बाद में भारत लौटने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जबकि भारत वास्तव में स्वर्ण पदक जीतने के लिए चला गया, मुंडा टीम के प्रबंधक से असहमति के कारण लीग मैचों के बाद भाग नहीं ले सका ।

उन्होंने 1939 में आदिवासी महासभा के अध्यक्ष का पद संभालने से पहले घाना सहित कई नौकरियां कीं, जिसका लक्ष्य "आदिवासी समस्याओं को हल करने के लिए पैन-आदिवासी एकजुटता"बनाना था । उनके नेतृत्व में, पार्टी ने आदिवासी बहुसंख्यक आबादी वाले एक अलग राज्य - झारखंड की भी मांग की ।
आजादी के बाद महासभा ने अपना नाम बदलकर 'झारखंड महासभा' कर लिया और चुनावी मैदान में उतर गई। 1952 के बिहार विधानसभा चुनाव में इसने 33 सीटें जीतीं। हालाँकि, इसकी लोकप्रियता अंततः कम हो गई। 1963 में, जयपाल मुंडा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पार्टी का विलय कर दिया, इसके चुनावी प्रक्षेपवक्र और 1962 में राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा झारखंड की मांग को अस्वीकार करने से निराश थे ।

″आदिवासी गणना के अनुसार″ मुंडा, अपने स्वयंम के परिवेश में ″अमीर″थे, इसके अलावा, चूंकि उनकी यात्राएं उन्हें देश से बहुत दूर ले गईं और, विशेष रूप से, उनकी 'भूमि' से, उन पर आदिवासियों की वास्तविक समस्याओं से अलग होने का आरोप लगाया गया । यह आरोप आदिवासी मुद्दों के लिए काम कर रहे संविधान सभा के एक अन्य सदस्य ए वी ठक्कर ने भी लगाया था। मुंडा के विपरीत, जो कांग्रेस के मुखर आलोचक थे और सभी 'बाहरी लोगों' के खिलाफ स्पष्ट शब्दों में बोलते थे, ठक्कर एक गांधीवादी और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य थे।

जयपाल सिंह मुंडा ने आदिवासियों के 'सामाजिक उत्थान' की ओर जोर देने वाले ठक्कर के समझौतावादी दृष्टिकोण को खारिज कर दिया, जिसमें आदिवासी लोगों के ″मूल निवासी″होने के नाते भूमि पर एक शक्तिशाली दावा और कुछ ″निर्देशात्मक″अधिकारों का समर्थन किया गया था। तीनों भाषणों में यह एक सामान्य विषय है। उनका कहना है कि आदिवासियों का उत्पीड़न 6,000 वर्षों से ″घुसपैठियों″द्वारा किया जाता रहा है – एक शब्द जिसमें न केवल ब्रिटिश, बल्कि भारत के सभी गैर-आदिवासी  निवासी शामिल हैं।

उनके भाषणों में एक अन्य महत्वपूर्ण विषय जनजातीय प्रतिनिधित्व की कमी है, विशेष रूप से मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों और बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति में। इस समिति का गठन 16 मई के कैबिनेट मिशन के बयान के अनुसार किया गया था । हालांकि मुंडा वास्तव में एक सदस्य थे, उन्होंने आदिवासी महिलाओं की कमी और इस तथ्य पर ध्यान दिया कि आदिवासी प्रतिनिधित्व देश में उनकी वास्तविक जनसंख्या के संबंध में व्यापक रूप से अनुपातहीन था ।

उनके भाषण सदियों से चले आ रहे दुर्व्यवहार को उजागर करते हैं, जिनमें से अंतिम आदिवासी-बहुसंख्यक क्षेत्रों का 'बहिष्कृत' या 'आंशिक रूप से बहिष्कृत' के रूप में ब्रिटिश वर्गीकरण था, जिसने उन्हें आधुनिक राजनीतिक प्रक्रिया से दूर रखा। वह ऐतिहासिक कमियों को ठीक करने के लिए अपने समुदाय के लिए सकारात्मक कार्रवाई की जोरदार मांग करता है। महत्वपूर्ण रूप से, वह इस बिंदु पर विधानसभा की निगरानी (या इससे भी बदतर, पाखंड) का आह्वान करने से नहीं कतराते हैं। उदाहरण के लिए, 27 अगस्त, 1947 के भाषण

में, उन्होंने पूछा कि अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित केंद्र सरकार की नियुक्तियों के लिए एक नीति की घोषणा क्यों की गई है, लेकिन उन आदिवासियों के लिए नहीं, जो ″सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद″हैं ।

भले ही उनके भाषण आदिवासियों के साथ किए गए व्यवहार और इस तथ्य के खिलाफ उनके गुस्से को व्यक्त करते हैं कि अधिकांश भारतीय – न केवल ब्रिटिश – इसके लिए जिम्मेदार थे, ऐसा लगता है कि वे पूरी तरह से विरोधात्मक रुख अपनाने से बचते हैं । संविधान सभा और भारत के नए नेतृत्व (विशेष रूप से जवाहरलाल नेहरू, जिनका वह कई बार नाम लेते हैं) में उनका दृढ़ विश्वास है । वह एक ऐसे राष्ट्र के रूप में भारत के लिए अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हैं जो एक न्यायसंगत और न्यायसंगत ढांचे पर पुनर्गठित होगा ।

यह दुख की बात है कि उनके विश्वास को उनके जीवनकाल में प्रमाणित नहीं किया जा सका। वह 2000 में झारखंड के निर्माण को देखने के लिए जीवित नहीं रहे, क्योंकि 1970 में 63 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया । हालांकि, इस लक्ष्य की उपलब्धि में देरी के बावजूद, उनका नेतृत्व आदिवासियों के अधिकारों की लड़ाई के शुरुआती चरणों में महत्वपूर्ण साबित हुआ । .

उनके हस्तक्षेप, अक्सर एक संविधान सभा के लिए असहज होते थे, जो एक 'एकीकृत राष्ट्र' के विचार को पेश करने की कोशिश कर रही थी, आदिवासी मामले की एक शक्तिशाली अभिव्यक्ति का गठन करती है।

यह यूं ही नहीं है कि जयपाल सिंह मुंडा को 'मरांग गोमके' (महान नेता) कहा जाता है । ( उद्धरण, जहां श्रेय नहीं दिया गया है, जयपाल सिंह मुंडा के हैं )

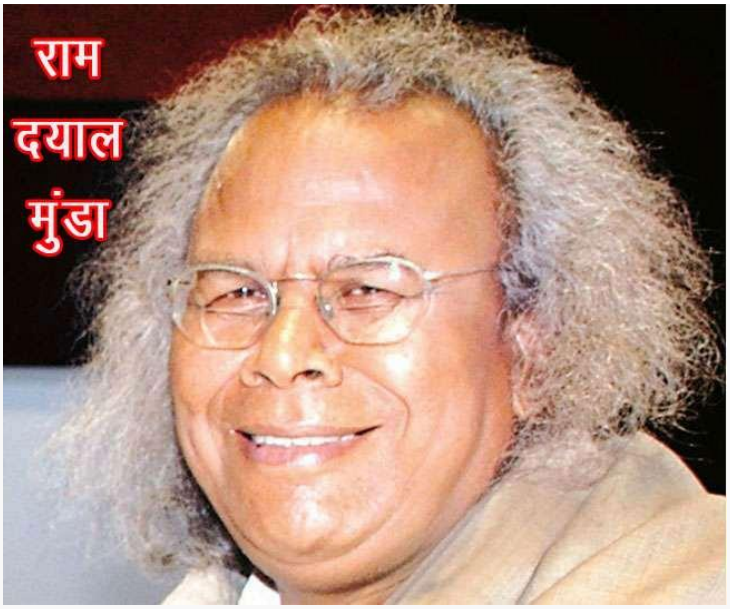


Ram Dayal Munda

https://joharjournal.org/ram-dayal-munda/

डॉ. राम दयाल मुंडा (1939–2011) एक प्रमुख विद्वान, शिक्षाविद, भाषाविद्, लेखक, अनुवादक, संगीतकार और आदिवासी सांस्कृतिक कार्यकर्ता थे। उनका जन्म 23 अगस्त 1939 को मुंडा आदिवासी परिवार में दिउरी गांव, रांची, झारखंड में हुआ था। 1963 में रांची विश्वविद्यालय से नृविज्ञान में परास्नातक पूरा करने के बाद, वह आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय गए और उसी विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने शिकागो, मिनेसोटा, रांची, ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी और सिरैक्यूज़ के विश्वविद्यालयों में संक्षिप्त रूप से पढ़ाया, और 1986 से 1988 तक रांची विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। मुंडारी, हिंदी और नागपुरी भाषाओं में उनके साहित्यिक कार्यों में हिसिर (1967), सेलेड ( 1967), कुछ नागपुरी गीत (1978), ईया नवा कानिको (1980), अन्य के साथ। उन्होंने ओशन ऑफ लाफ्टर (1975), कल्याणी (1976), होली मैन फ्रॉम जमानिया (1977), ध्रुव स्वामिनी (1979), तितली (1980), द सन सारथी (1981) जैसे कार्यों के साथ हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी से भी अनुवाद किया ), बिरसा मुंडा (2000), आदि उनके सबसे उल्लेखनीय विद्वतापूर्ण कार्य प्रोटो-खेरवारियन साउंड सिस्टम (1967), मुंडारी व्याकरण (1979), आदि-धर्म (2000), झारखंड आंदोलन (एस. बसु मलिक के साथ, 2000) थे। उनके कई पत्र प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाओं में भी प्रकाशित हुए थे।

डॉ. मुंडा ने दक्षिण एशियाई लोक कलाकारों के रूप में जाने जाने वाले कलाकारों की एक मंडली को एक साथ लाकर जनजातीय संगीत और नृत्य को बढ़ावा दिया, जिसने भारत और विदेशों में कई सांस्कृतिक उत्सवों में प्रशंसा हासिल की। भारतीय आदिवासी साहित्य, संगीत और नृत्य में उनके योगदान के लिए, डॉ. मुंडा को 2007 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 2010 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 30 सितंबर 2011 को रांची में उनका निधन हो गया।

**The Pain of Development (Vikas Ka Dard)**

I have become a jackal
On the run
Towards the city
Before dying.
I feel as if
A gigantic saal tree fell on me
As someone was sawing it
For use in the development of the country.

Now more speedily
Will this work be done.
Development experts
And mighty nations of the world
Will support my country.
How does it matter that
My country is neck-deep in debt?
We shall borrow money to
Repay interest on the
Money already taken.
They say, 'Eat well, even if
Good food is bought with
Loan already taken.'

For how long will I have to
Bear the pain of development
Or is it that I will be done to death
Before attaining development?

(Yudhrat Aam Aadmi, 2001, 62. Translated from the Hindi by Mridula Rashmi Kindo)

**The Return (Vapsi)**

That day Bandhan had felt good.
After months of confusion and uncertainty
He had decided
To return to his old village home;
When the train had whistled to depart,
He had felt a strange shiver down his spine.
Working for the past ten years in the tea gardens of Assam
Had shrunk to a few moments;
His eyes could now see
An entirely different village
That engulfed him in its magical shadow.

The red soil on the path leading to his village
Would have become metalled now;
Below the tamarind tree and next to the dance-arena
Would have come up a school
And amidst the beats of drums,
The shouts of children
Would be presenting a new spectacle;
Besides, the people too would have assumed unfamiliar ways.

And what would that exorcist Rando Guru
Be doing now?
It is certain that his rituals
Would have lost effect
Beside the hospital medicines and injections;
But what about grandmother's weaving of the mats?
Perhaps one would still be hearing in the dead of night
The occasional barking of dogs in the village….

And then he woke up from his reverie.
He saw in front of him
A loneliness that made his heart skip a beat;
Not that he was alone,
For there was no dearth of folks in the village;
People were walking to and fro;
The air was filled with a sense of urgency.

Bandhan kept trying to recognize every face
But in return each face looked at him
As if he was the question mark.
Bandhan found in front of him
A motionless time separating
The moments of then from now.

Then, he had run away leaving the village behind;
Now, the village has run away
Leaving him behind!

(Yudhrat Aam Aadmi, 2001, 63-64. Translated from the Hindi by Mridula Rashmi Kindo)

राम दयाल मुंडा

विकास का दर्द ( विकास का दर्द )

मैं सियार बन गया हूँ मरने से पहले शहर की ओर

भागता हूँ । मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई विशाल साल का पेड़ मुझ पर गिर पड़ा हो जैसे कोई उसे देख रहा हो देश के विकास में उपयोग के लिए।

अब और तेजी से

यह काम होगा।

विकास विशेषज्ञ

और दुनिया के ताकतवर देश

मेरे देश का साथ देंगे।

इससे क्या फर्क पड़ता है कि

मेरा देश कर्ज में डूबा हुआ है? हम पहले से लिए गए धन पर ब्याज चुकाने

के लिए धन उधार लेंगे । वे कहते हैं, 'अच्छा खाओ, भले ही अच्छा खाना पहले से लिए गए ऋण से खरीदा गया हो।'

कब तक सहूंगा विकास का दर्द या

विकास पाने से पहले मुझे मौत के घाट उतार दिया जाएगा?

द रिटर्न ( वाप्सी )

उस दिन बंधन को अच्छा लगा था।

महीनों की असमंजस और अनिश्चितता के बाद

उसने

अपने पुराने गाँव घर लौटने का फैसला किया था;

जब ट्रेन ने प्रस्थान करने के लिए सीटी बजाई थी, तो

उसे अपनी रीढ़ के नीचे एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई थी।

असम के चाय बागानों में पिछले दस सालों से काम करना

चंद लम्हों के लिए सिमट गया था; उसकी आँखें अब

एक पूरी तरह से अलग गाँव

देख सकती थीं जिसने उसे अपनी जादुई छाया में घेर लिया था।

उसके गाँव जाने वाले रास्ते की लाल मिट्टी

अब पक्की हो गई होगी;

इमली के पेड़ के नीचे और नृत्य-क्षेत्र के पास

स्कूल होता

और नगाड़ों की थाप के बीच

बच्चों की किलकारियां

एक नया तमाशा पेश कर रही होतीं;

इसके अलावा, लोगों ने भी अपरिचित तरीके अपनाए होंगे।

और वह ओझा रंडो गुरु

अब क्या कर रहा होगा? अस्पताल की दवाओं और

इंजेक्शन के अलावा उनके संस्कारों का असर

निश्चित है ; लेकिन दादी माँ द्वारा चटाई बुनने का क्या?

शायद अब भी रात के सन्नाटे में गाँव में कभी-कभी

कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई दे रही होगी...

# Part I

# Forests of Jharkhand

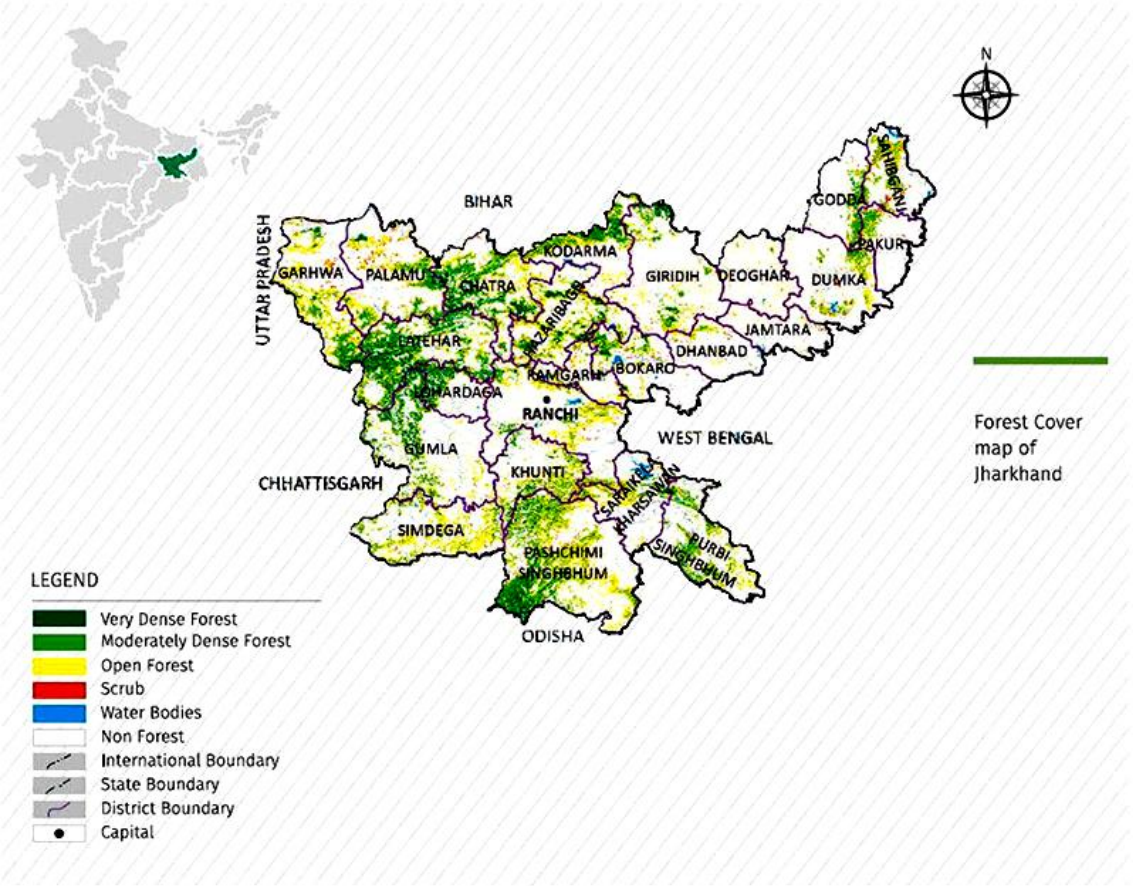


Forest Map of Jharkhand[1]

[1]https://forest.jharkhand.gov.in/Reports_2017/forestcovermap.aspx

# वन:

## आजीविका के लिए एनटीएफपी की प्रासंगिकता:

https://jhamfcofed.com/abut/index.htm

झारखंड समृद्ध वन संपदा से संपन्न है। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में झारखंड देश के कुल वन क्षेत्र का 3.4% है और सभी राज्यों में 10वें स्थान पर है। वनों में कई महत्वपूर्ण गैर-काष्ठ वन उत्पाद (NWFP) पाए जाते हैं | जैसे - तेंदू पत्ता या बिडी पत्ता, साल बीज, हर्रा, महुआ फूल, इमली (इमली), वन तुलसी आदि।

मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट का अनुमान है कि वनों के मूल्य का 96% तक गैर-इमारती वन उत्पाद (एनटीएफपी) या लघु वन उत्पाद (एमएफपी) और सेवाएं (एमईए 2005) से प्राप्त होता है। 5,000 से अधिक वाणिज्यिक वन उत्पाद गैर-लकड़ी उत्पाद हैं, जिनमें फार्मास्यूटिकल्स और भोजन शामिल हैं।

## वन आश्रित समुदायों के लिए वन का महत्व:

https://jhamfcofed.com/w_jham/index.htm

झारखंड में गरीब लोगों के लिए आजीविका के स्रोत के रूप में वन: झारखंड में लगभग 29% क्षेत्र

पूरे भारत में 23% की तुलना में झारखंड वनाच्छादित है। झारखंड देश के कुल वन आवरण का 3.4% है और सभी राज्यों में 10वें स्थान पर है । 2005-06 में राज्य के जीएसडीपी में वनों का योगदान लगभग 1.3% था जो 2001-02 के आधे से भी कम है । 2000 में राष्ट्रीय औसत 26% के मुकाबले झारखंड का गरीबी अनुपात 44% था। हालांकि ग्रामीण गरीबी 49% पर सभी राज्यों में सबसे अधिक थी। 49% ग्रामीण गरीबी में से 75% लोग ऐसे हैं जो या तो जंगल के अंदर या आसपास रहते हैं। इन 75% गरीबी से ग्रसित लोगों का जीवन पूरी तरह से वन संसाधनों पर निर्भर करता है क्योंकि वन उनकी आजीविका का मुख्य स्रोत हैं। यह खराब मौसम के दौरान अधिक होता है। बेहद गरीब ग्रामीण लोग जंगलों से लकड़ी इकट्ठा करते हैं और उन्हें शहरी क्षेत्रों में ले जाते हैं जहां वे उन्हें औने-पौने दामों पर बेचते हैं ।

## एफआरए का वादा और क्षमता

2016 में लाए गए वादे और संभावित रिपोर्ट के अनुसार, पारंपरिक ग्रामीण सीमाओं के तहत क्षेत्र जहां एफआरए स्वचालित रूप से लागू होना चाहिए वह 21,19,095.9 हेक्टेयर है । हालाँकि, मार्च 2022 तक, केवल 1,04,066.86 हेक्टेयर को FRA के तहत मान्यता दी गई थी यानी संभावित क्षेत्र का केवल 4.91% ही मान्यता प्राप्त है । एफआरए के संबंध में आधिकारिक साइट पर दिए गए विवरण बहुत कम या कोई दावा खारिज नहीं होने और कोई भी लंबित नहीं होने का संकेत देते हैं । जेएमकेयू उपलब्ध वर्णन के अनुसार जमीन पर सच्चाई अलग है । जनजातीय मंत्री को प्रस्तुत जेएमकेयू मामले के अध्ययन से संकेत मिलता है कि दावों की गैर-मान्यता वन अधिनियम 1927 और वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत कथित उल्लंघन के लिए स्थानीय आबादी के अपराधीकरण से संबंधित है । संक्षेप में इसका मतलब है कि इन क्षेत्रों में लोगों के पास एफआरए के तहत कोई अधिकार नहीं है ।

## मनुष्य/पशु संघर्ष

https://nativepicture.com/gram-sabha-local-community-governance-preserves-the-forests-of-jharkhand/

पर्यावरणीय व्यवधान ने वन्यजीव गलियारों, विशेष रूप से हाथियों के प्रचालन क्षेत्र पर अतिक्रमण कर लिया है, जिससे उनके मौसमी आवागमन में बाधा आ रही है । उनकी विशालता ने एक ऐसा प्रभाव पैदा किया है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है । खनन द्वारा बनाए गए बड़े गड्ढों से बचने के लिए, हाथी स्थानीय गांवों की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे मानव-हाथी संघर्ष में वृद्धि हो रही है । संकटग्रस्त प्राणियों द्वारा घर, खेत और आजीविका को नष्ट किया जा रहा है । झारखंड के गांवों के स्थानीय लोग हाल ही में 15 साल पहले हाथियों और ग्रामीणों के बीच सकारात्मक संबंधों का वर्णन करते हैं। अतीत में, हाथियों ने आज के गाँवों को बार-बार नुकसान नहीं पहुँचाया । अकेले झारखंड में हाथियों के संघर्ष से तीन सौ से अधिक लोगों की मौत की सूचना है। अब, फ़सल की कटाई के समय ही झुंड अक्सर गाँवों को परेशान करते हैं, आजीविका के नुकसान को बढ़ाते हैं और भय पैदा करते हैं ।

# Part II

# Water Resources of Jharkhand

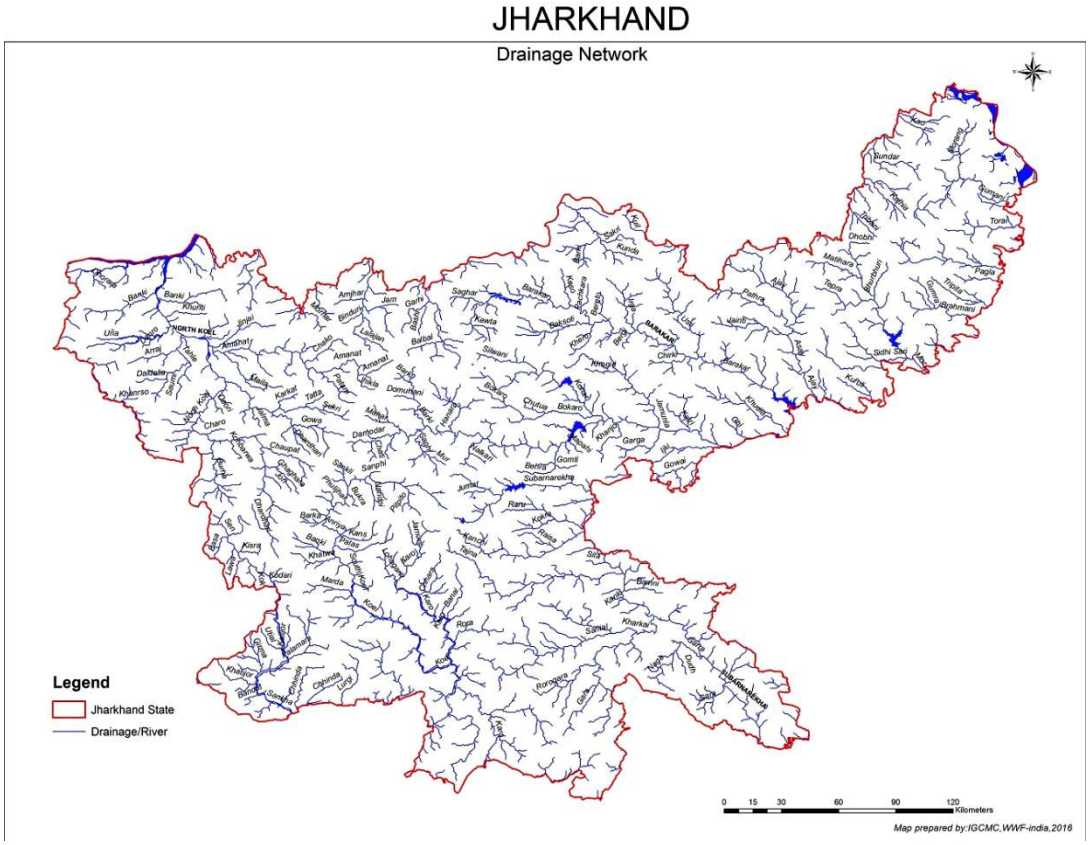


Drainage map of Jharkhand

https://indiariversblog.wordpress.com/2017/05/16/jharkhand-rivers-profile/

https://sandrp.in/2017/05/16/jharkhand-rivers-profile/

## झारखंड की नदियों का प्रदूषण:

क्षेत्र में चल रहे बड़े पैमाने पर खनन कार्यों ने कई क्षेत्रों में भू जल ( स्तर ) तालिका पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है, जिसके परिणामस्वरूप आसपास के गांवों के कुओं में पानी की भारी कमी आई है । इसके अलावा, खनन क्षेत्रो स्थलों से निकलने वाले बहिस्राव ने क्षेत्र की धाराओं और भूमिगत जल को गंभीर रूप से प्रदूषित कर दिया है । एसिड माइन ड्रेनेज, कोल हैंडलिंग प्लांट्स, कोलियरी वर्कशॉप्स और माइन साइट्स से निकलने वाले लिक्विड और कोल वाशरीज से सस्पेंडेड सॉलिड्स ने इस क्षेत्र में गंभीर जल प्रदूषण पैदा किया है, जिससे मछली और जलीय जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ।

*Table showing selected Polluted River Stretches in Jharkhand*

| S.no. | River name | Stretch Identified. | Towns Identified. | Approx length of the stretch (in Km) |
|---|---|---|---|---|
| **1** | Bokaro | Bilyotara To Jarandi | Bilyotra, Gumia | **8** |
| **2** | Damodar | Phusro Road Bdg To Turio | Phusro,Bhandaridah, Dhanbad | **12** |
| **3** | Jumar | Kanke Dam To Kadal | Ranchi, Morabadi | **10** |
| **4** | Karo | Lohojimi To Balagoda | Balagoda,Lohojimi | **16** |
| **5** | North Koel | Basiadam To Rehla | Ranchi,Daltonganj | **6** |
| **6** | Koel | Daltanganj To Rehla | Kandi, Bisrampur, Majhiaon | **25** |
| **7** | Sankh | Kongserabasar To Bolba | Kusumdegi,Machhkata | **10** |
| **8** | Subarnarekha | Hatia Dam To Jamshedpur | Ranchi, Namkum. | **120** |

***A report by Dr. Nitish Priyadarshi***

# Part III

# Energy sector in Jharkhand

2022 में झारखंड की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता 2.735 मेगावाट थी, जिसमें से अधिकांश कोयले से थी। कोयले का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक होने के बावजूद, झारखंड में बिजली उत्पादन में कमी है क्योंकि अधिकांश कोयला राज्य से बाहर निर्यात किया जाता है। राज्य लगातार बिजली कटौती का अनुभव करता है क्योंकि कोयला कंपनियां राज्य बिजली बोर्ड को आपूर्ति करने से मना कर देती हैं | जब तक कि सभी बकाया का भुगतान नहीं

किया जाता है । नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के मामले में भी झारखंड अपने लिए निर्धारित लक्ष्यों से भी पीछे है. आबादी के एक बड़े वर्ग के रोजगार और आजीविका के सहायक रूपों के लिए इस पर निर्भर होने के कारण थर्मल बिजली उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की नीति के साथ प्रमुख चिंताएं हैं ।

वहीं कोयला कंपनियों के उन गांवों से संबंध जहां कोयले का खनन हो रहा है, बहुत अच्छे नहीं हैं। विस्थापन, जल स्रोतों की कमी, धूल प्रदूषण, आग और वनों की कटाई से संबंधित मुद्दे ज्वलंत मुद्दे हैं, कई कार्यकर्ताओं/स्थानीय समुदाय के सदस्यों ने जनविरोधी उपायों का विरोध करते हुए अपने प्राणों की आहुति भी दी है । कोयला कंपनियों को कोयला खदानों के आसपास पानी और बिजली से संबंधित अस्थायी सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए जाना जाता है, जब कोयला समाप्त हो जाता है तो ऐसे प्रावधानों को समाप्त कर दिया जाता है ।

इसलिए यह स्पष्ट नहीं है कि स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं और स्थानीय मूल्यवर्धन के लिए आजीविका को जोड़ने वाली एक स्पष्ट नीति क्यों नहीं बनाई जा सकती है, क्योंकि इस क्षेत्र में समृद्ध जैव विविधता संसाधन हैं, जिन पर अधिकांश गरीब और हाशिए के समुदाय निर्भर हैं।

# Part IV

# Minerals

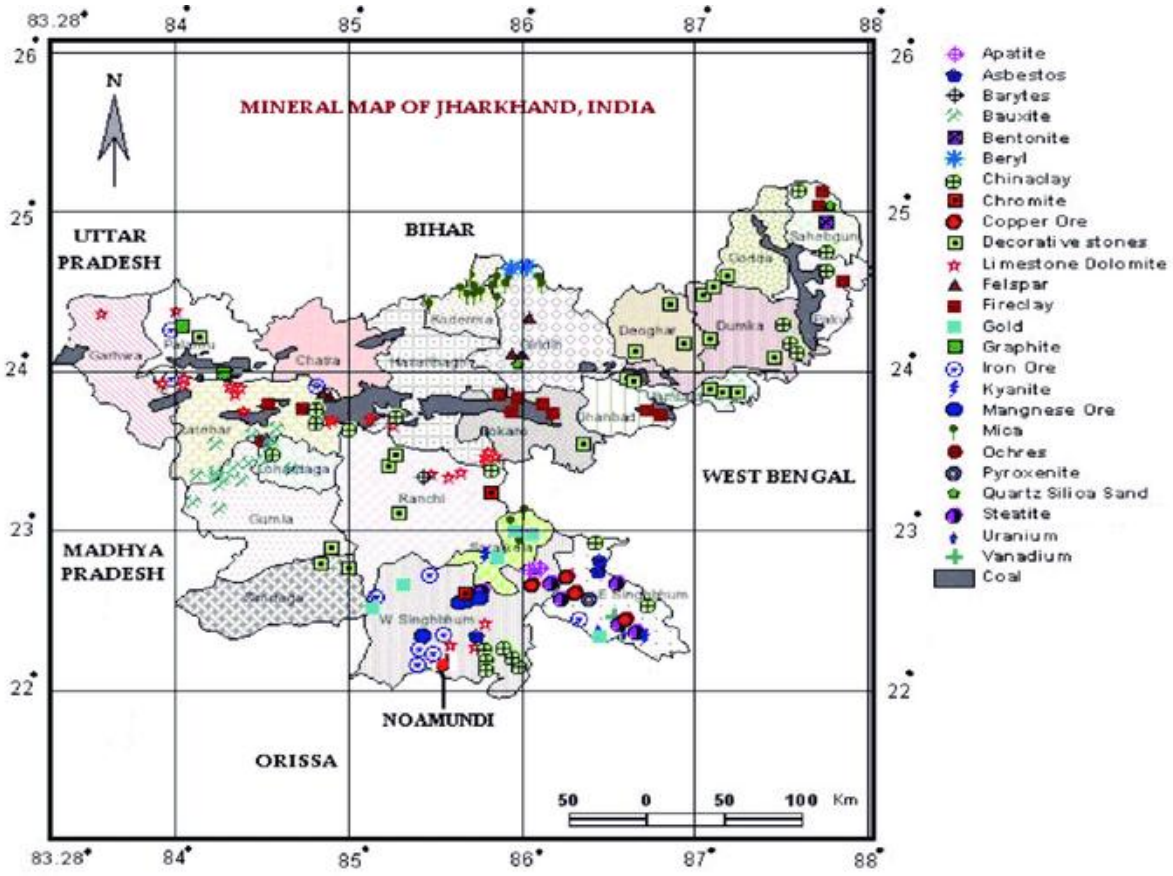


Mineral Map of Jharkhand: Amiva Patel

## खनिज स्रोत

https://www.jharkhand.gov.in/home/AboutMinerals#:~:text=The%20state%20stretches%20over%2079%2C714,total%20mineral%20resources%20of%20India.

झारखंड अपार खनिज क्षमता और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के प्राकृतिक उपहार के साथ एक धन्य भूमि है। झारखंड राज्य देश के खनिज मानचित्र पर एक मजबूत स्थिति में है । दुनिया के किसी भी क्षेत्र में इतने निकट के क्षेत्र में इतने विशाल खनिजकरण का उपहार नहीं है जितना कि झारखंड में है। राज्य में ऊर्जा, लौह, अलौह, उर्वरक, औद्योगिक, दुर्दम्य, परमाणु, रणनीतिक, कीमती और अर्ध-कीमती समूहों के खनिजों के संभावित भंडार हैं। राज्य 29.61% वन क्षेत्र के साथ 79,714 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्र में फैला है और भारत के कुल खनिज संसाधनों का लगभग 40% का मालिक है। राज्य कोयले के भंडार में प्रथम स्थान पर, लोहे में दूसरे स्थान पर, कॉपर अयस्क रिजर्व में तीसरे स्थान पर, बॉक्ससाईट रिजर्व में सातवें स्थान पर है और प्राइम कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक है । वर्तमान में झारखंड राज्य सालाना 15,000 करोड़ रुपये के लगभग 160 मिलियन टन विभिन्न प्रकार के खनिजों का उत्पादन कर रहा है और लगभग 3,500 करोड़ रुपये का खनिज राजस्व उत्पन्न कर रहा है। कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट, यूरेनियम, चूना पत्थर, डोलोमाइट, पाइरोक्सेनाइट, क्वार्टज और क्वार्टजाइट के भंडार पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। चाइना क्ले, फायरक्ले, मैग्नेटाइट, ग्रेफाइट, कानाइट, फेल्डस्पार, माइका और सजावटी पत्थरों के भंडार प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं । अंडालूसाइट, मैंगनीज, क्रोमाइट, बेरिल, टैल्क, गोल्ड, बेंटोनाइट के भंडार कम मात्रा में उपलब्ध हैं ।

# Part V

# Agriculture in Jharkhand

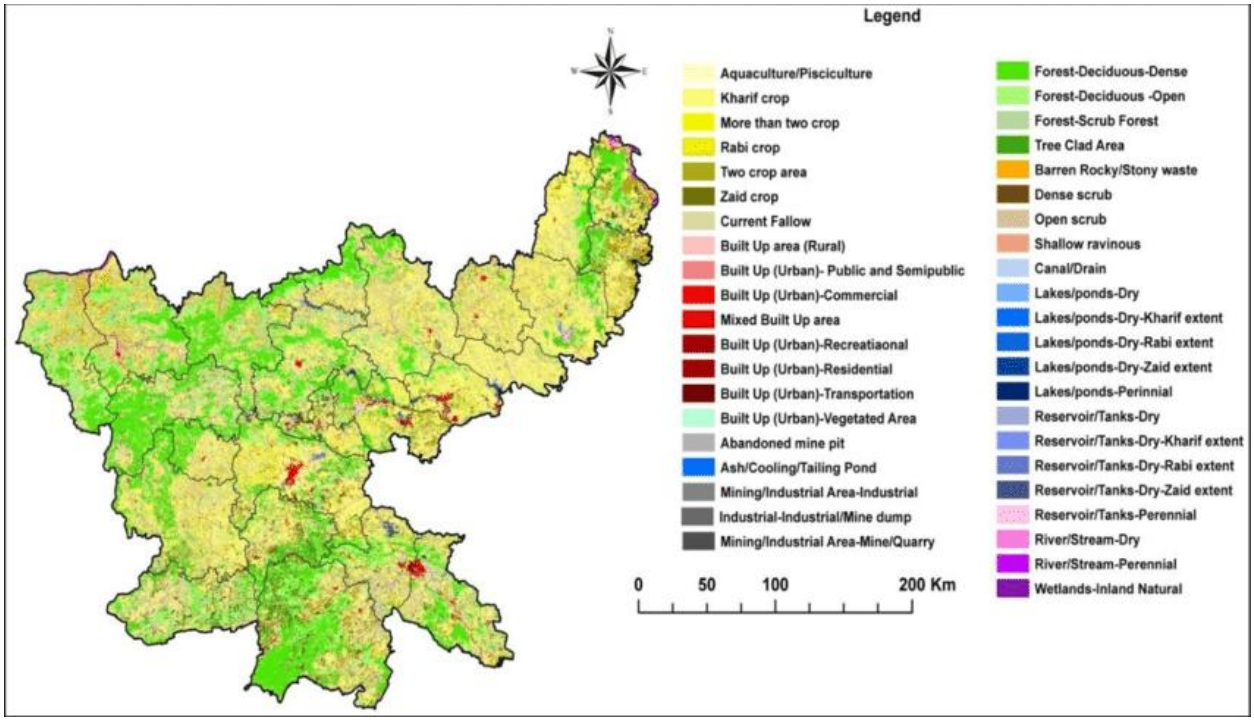


Land Use Land Cover Map of Jharkhand: Neeraj Sharma

## कृषि से संबंधित मुद्दे:

झारखंड में केवल 22% भूमि (17.63 लाख हेक्टेयर) कृषि के लिए समर्पित है, जिसमें से 83% (14.63 लाख हेक्टेयर) वर्षा आधारित है। हालाँकि कुल कार्यबल का 78% गाँव में रहता है और 75% कृषि पर निर्भर है। 77.83% भूमि के साथ या तो वन (29.3%), परती (25.4%), खेती के लिए उपलब्ध नहीं (17.1%), या अन्य अनुपजाऊ भूमि जैसे चरागाह (6.0%), सामान्य रूप से आम और जंगलों की प्रासंगिकता विशेष रूप से लोगों की जीवन समर्थन प्रणालियों को कमजोर नहीं किया जा सकता है ।

https://www.outlookindia.com/outlooktraveller/explore/story/71460/cuisine-as-an-integral-part-of-adivasi-culture-and-identity-in-jharkhand

आदिवासी समुदाय, अपनी समृद्ध सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं के अलावा, अत्यधिक विविध भोजन प्रथाओं का अभ्यास करते हैं जो स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों और तकनीकों पर आधारित हैं। ऐसी आदिवासी खाद्य प्रणालियाँ इन समुदायों की संप्रभुता और आत्मनिर्भरता को बनाए रखने में सहायक रही हैं। उन्होंने अपने आहार को समृद्ध करने के लिए और कैल्शियम, लोहा, खनिज और विटामिन की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कई प्रकार की सब्जियां और कंद उगाते है , जंगली कंद मूल, फल, फुल उनके जिविका का आधार हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि आदिवासी भोजन रोग और विकृति से उच्च स्तर की प्रतिरक्षा प्रदान करता है।

औषधीय पौधों और हर्बल उत्पादों का दायरा और भी बड़ा है। नृवंशविज्ञान पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के अनुसार, आदिवासी समुदाय खाद्य पौधों सहित पौधों की 9,000 से अधिक प्रजातियों के उपयोग से परिचित हैं, जबकि विशेष रूप से उपचार के उद्देश्य से वे पौधों की लगभग 7,500 प्रजातियों के उपयोग को जानते हैं ।

https://joharjournal.org/tribal-cuisine-of-jharkhand/

मछली विशेष रूप से मानसून के मौसम के दौरान आदिवासियों द्वारा पसंद की जाती है । गाँवों में तालाबों और नदियों में पकड़ी जाने वाली मछलियों को बनाना बहुत ही सरल है, जिसमें बहुत कम या कोई मसाला नहीं होता है। इसलिए, स्वाद मटमैला और स्वादिष्ट होता है। मांस के मामले में भी वे बहुत कम मसालों में पकाना पसंद करते हैं। तालाबों और

नदियों में पाई जाने वाली बुदनू, मुरगई, गेटू, पोथी, गिरसा, जीयस, मुगरी, टेंगना, पेरवा, कुसमा, पत्तलचट्टा, झिला कुटरी आदि मछलियाँ बहुत हल्के मसालों के साथ पकाई जाती हैं। मछली की सभी किस्मों को भी सुखाया जाता है और बाद में करी में पकाने के लिए रखा जाता है। मछली और पक्षी के मांस को भी टहनियों के टुकड़ों के साथ पत्तियों के अंदर सील करके बारबेक किया जाता है। आदिवासी ज्यादातर मवेशी, बकरी, सूअर, मुर्गियाँ, कबूतर और खरगोश पालते हैं जिन्हें भोजन के रूप में भी खाया जाता है ।